सं. जेड-14014/2/2023-जीसी एण्ड पार्लि.(ई-3012849)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011,

दिनांक: 22.01.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिसंबर, 2023 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को दिसंबर, 2023 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त।

विजय कौशिक

(विजय कौशिक)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी माननीय सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
2. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा इस्पात) के निजी सचिव।

दिसंबर, 2023 के दौरान भूमि संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार

1. भूमि संसाधन विभाग द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में दिनांक 22.12.2023 को "वाटरशेड परियोजनाओं में हरित अर्थव्यवस्था के लिए कैक्टस" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय ने वीसी के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। भूमि संसाधन विभाग ने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत शूलरहित कैक्टस की खेती और उसके आर्थिक उपयोग के संवर्धन में सहयोग पर आईसीएआर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, आईसीएआरडीए और राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 15 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 200 प्रतिनिधि, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञों आदि ने बैठक में भाग लिया।

2. सचिव, भूमि संसाधन विभाग ने दिनांक 29.12.2023 को मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में "भूमि और संपत्ति" संबंधी सत्र में भाग लिया।

3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं में सेचुरेशन प्राप्त करने हेतु ऑउटरीच कार्यकलापों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंग के रूप में, भूमि संसाधन विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र ग्रामों को अभिनन्दन पत्र (सम्मान प्रमाण पत्र) वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में 100% लक्ष्य प्राप्त करने पर (गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अनुसार) ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर के अधिकारियों जैसे पटवारी/लेखपाल/मंडल और ग्राम पंचायत के अधिकारी जैसे सरपंच आदि को सम्मानित करना, शामिल है। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति के अनुसार, 91201 ग्राम पंचायतों में अभिनंदन पत्र वितरित किए गए। इस महीने के दौरान सचिव (एलआर) एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने झारखंड, ओडिशा और त्रिपुरा के चयनित ग्रामों का दौरा किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया।

4. दिनांक 20.12.2023 को सचिव (एलआर) की अध्यक्षता में कोर तकनीकी सलाहकार समूह (सीटीएजी) की बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से प्राप्त सर्वेक्षण संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई और तकनीकी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

5. कर्नाटक राज्य तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में दिसंबर, 2023 में विशिष्ट भू-खंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन)/ भू-आधार आरंभ किया गया है तथा उन्होंने लगभग **85 लाख** भू-खंडों को भू-आधार प्रदान किया है। अभी तक, 29 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने यूएलपीआईएन संख्या को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, 4 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों नामतः पुद्दुचेरी, तेलंगाना, मणिपुर

तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रायौगिक परीक्षण किया गया है। जहां तक राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) का संबंध है, इसे 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरंभ किया गया तथा 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने यूजर इंटरफेस/एपीआई के माध्यम से राष्ट्रीय पोर्टल पर डाटा साझा करना आरंभ किया है।

6. संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएम) की अध्यक्षता में दिनांक 07.12.2023 को रिवार्ड कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक समीक्षा मिशन की बैठक आयोजित की गई। विश्व बैंक के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, आईसीआरआईएसएटी, एमएएनएजीई तथा एनआरएसए ने बैठक में भाग लिया।

7. सचिव (एलआर) ने भूमि अभिलेख डेटाबेस के साथ ई-न्यायालयों के एकीकरण के संबंध में सचिव, न्याय विभाग और उनकी टीम के साथ बैठक की।

8. भूमि संसाधन विभाग ने 19-20 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआर&पीजी) द्वारा आयोजित 'सुशासन सप्ताह' आयोजन में भाग लिया। भूमि संसाधन विभाग ने सुशासन प्रदर्शनी में भाग लिया, जिसमें विशेष अभियान 3.0 के दौरान विभाग द्वारा किए गए 'सर्वोत्तम प्रथाओं' पर प्रकाश डाला गया।

9. डेटा की गुणवत्ता में सुधार के तरीकों को खोजने के लिए दिनांक 06.12.2023 को विभाग की डेटा कार्यनीति इकाई की एक बैठक आयोजित की गई थी।

10. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत कुल 6382 परियोजनाओं {8214 (स्वीकृत)-1832 (राज्य को हस्तांतरित)} में से अब तक 6376 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। अब तक 6120 परियोजनाओं का एंड लाइन मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है।

11. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के विभिन्न घटकों की प्रगति (संचयी) की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है: -

i. **6,25,137** ग्रामों के भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा किया गया।

ii. **5,060** एसआरओ के रजिस्ट्रीकरण के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा किया गया।

iii. **2,52,51,446** भूकर मानचित्रों/एफ़एमबी/टिप्पनों के डिजिटीकरण के कार्य को पूरा किया गया।

iv. भूमि अभिलेखों के साथ **4,669** एसआरओ के एकीकरण का कार्य पूरा किया गया।

v. **3,461** तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना का कार्य पूरा किया गया।

*****